भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1257
मंगलवार, 11 फ़रवरी, 2025/22 माघ, 1946(शक) को उत्तरार्थ

आंध्र प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियां

1257. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आंध्र प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों की कुल संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने सहकारी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) आंध्र प्रदेश में सहकारिता के अंतर्गत कितने शहरी बैंक हैं;
- (घ) क्या इनमें से किसी शहरी बैंक को लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में परिवर्तित किए जाने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) आन्ध्र प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 27 जनवरी 2025 तक कार्यरत सहकारी समितियों की कुल संख्या का जिलावार विवरण **अनुबंध-1** में संलग्न है।

(ख) सरकार ने सहकारी समितियों के विकास के लिए पूरे देश में कई योजनाएँ शुरू की हैं। निम्नलिखित योजनाएँ सरकार द्वारा लागू की गई हैं :

1. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण:** पैक्स को सुदृढ़ करने हेतु 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है। इस परियोजना के अधीन 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 67,930 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं। 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद कर ली गई है तथा कुल 50,455 पैक्स को ERP पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है।

2. **सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:**सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदमों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु परियोजना को मंजूरी दे दी है । इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को उनकीउपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी ।पायलट परियोजना के तहत 11 राज्योंके 11 पैक्स में गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।
3. **सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण हेतु 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का शुभारंभ:** सरकार ने NCDC के माध्यम से एथनॉल संयंत्र या को जेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या फिर तीनों के लिए एक योजना आरंभ की है । अब तक, मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी को 875 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 375 करोड़ रुपये) जारी किया है और अब तक, एनसीडीसी ने 44 सीएसएम को 9,169.76 करोड़ रुपये के 80 ऋण स्वीकृत किए हैं।
4. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण:** दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है । नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है । अब तक 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इसके अलावा हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 5.08 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।
5. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की व्यापकता और पहुंच का विस्तारण:**NCDC ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे स्वयं सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार', दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' । चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में NCDC द्वारा 84,673.70 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता का संवितरण किया गया है ।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, 27 जनवरी 2025 तक, आंध्र प्रदेश में कुल 35 शहरी सहकारी बैंक कार्यरत हैं।

(घ) वर्तमान में, आंध्र प्रदेश में कोई भी शहरी सहकारी बैंक लघु वित्त बैंकों (SFBs)में परिवर्तित किए जाने पर विचाराधीन नहीं है।

(ङ) आंध्र प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का विवरण निम्नलिखित है:

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	पैक्सके कम्प्यूटरीकरण के लिए स्वीकृत राशि	NCDC द्वारा स्वीकृत राशि
1	2022-23	14.93	11338.85
2	2023-24	22.84	14222.28
3	2024-25	18.12	18503.42

अनुबंध-I**आंध्र प्रदेश में जिलावार कार्यरत सहकारी समितियों की कुल संख्या**

क्र. सं.	जिला	संस्थाओं की संख्या
1	अलुरी सितारामा राजु	60
2	अनाकापल्ली	592
3	अनंतपुर	313
4	अन्नमैया	250
5	बापटला	502
6	चित्तूर	315
7	पूर्व गोदावरी	649
8	एलुरू	864
9	गुंटूर	260
10	काकिनाडा	581
11	कोना सीमा	875
12	कृष्णा	689
13	कुर्नूल	481
14	नंदयाल	184
15	एनटीआर	632
16	पालनाडु	546
17	पार्वतिपुरम मण्यम	150
18	प्रकाशम	737
19	SPSR नेल्लोर	679
20	श्री सत्य साई	283
21	श्रीकाकुलम	439
22	तिरुपति	466
23	विशाखापट्टनम	530
24	विजयनगरम	361
25	पश्चिम गोदावरी	667
26	Y.S.R.	589
कुल		12694

स्रोत: राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD), 27 जनवरी 2025 तक